प्रस्ताव
42
सार्वजनिक रिकॉर्ड। खुली बैठकें। स्थानीय संस्थाओं को राजकीय प्रतिपूर्ति। विधायी संवैधानिक संशोधन।

★ प्रस्ताव 42 के पक्ष में तर्क ★

हर किसी ने यह कहावत सुनी है "आप सिटी हॉल से नहीं लड़ सकते हैं।" पता चला है कि यह साफ झूठ है। लाखों California वासी काउंटियों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स, वाटर एजेंसियों, और प्रत्येक प्रकार की सरकारी संस्था के सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों से इस आशय से उत्तर चाहते हैं, ताकि वे हासिल जानकारी का उपयोग राजनीतिक प्रक्रिया में प्रवेश करने और सार्वजनिक नीति को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करने के लिए कर सकें।

California सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम जैसे सशक्त साधन नागरिकों और व्यवसायों को प्रभावी समर्थक होने और समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड प्राप्त करने की सामर्थ्य देते हैं। Ralph M. Brown खुली बैठक कानून सिटी काउंसिल, बोर्ड ऑफ सुपरवाईजर, स्कूल बोर्ड, और विशेष डिस्ट्रिक्ट की बैठकों के दौरान नीति तैयार किये जाते समय हमें उस कक्ष में होने और हमारी बात सुनी जाने का अधिकार देता है।

2004 में, California वासियों को सार्वजनिक रिकॉर्ड की सुलभता और स्थानीय सार्वजनिक निकायों में भाग लेने के इन कानूनों को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया गया जब 82 प्रतिशत से भी अधिक मतदाताओं ने इस राज्य संविधान में एक संशोधन को मंजूरी दे दी जिसमें आंशिक रूप से कहा गया है: "लोगों को लोगों के कारोबार के संचालन से सम्बन्धित जानकारी की सुलभता का अधिकार है, और, इसलिए, सार्वजनिक निकायों की बैठकें और सरकारी अधिकारियों व एजेंसियों के लेखन रिकॉर्ड सार्वजनिक जाँच के लिए खुले होंगे।"

हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, इन उत्कृष्ट कानूनों के महत्वपूर्ण को खतरा उत्पन्न हो गया था जब राज्य वित्तीय संकट से ग्रस्त था। संक्षेप में, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सुलभता के जनसामान्य के नागरिक अधिकार का अनुपालन करने की स्थानीय लागतों के लिए सरकार को राज्य की वित्तीय सहायता की राशि और उसके स्तर को लेकर लम्बेसमय से असहमति चली आ रही है। कई बार राज्य की बजट प्रक्रिया में लिये गये कड़े निर्णयों के नाते इन कानूनों के मुख्य प्रावधान स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए वैकल्पिक बन गये हैं। हालाँकि अधिकांश सरकारों ने वित्तीय तनाव की इन संक्षिप्त अवधियों के दौरान अनुपालन करना जारी रखा, लेकिन जनसामान्य के मौलिक अधिकार स्थानीय अधिकारियों की कृपाओं पर निर्भर नहीं होने चाहियें।

प्रस्ताव 42 स्पष्ट करेगा कि स्थानीय सरकारी संस्थाएं, न कि राज्य, हमारे सुलभता सम्बंधी कानूनों के अनुपालन से जुड़ी लागतों के लिए जिम्मेदार हैं। यह प्रस्ताव सार्वजनिक रिकॉर्ड और बैठकों की सुलभता सुनिश्चित करेगा जो कि सार्वजनिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने और उससे लड़ने के लिए आवश्यक है, जैसा कि सिटी ऑफ Bell के नागरिकों के द्वारा उस समय अनुभव किया गया था जब सरकारी अधिकारी आपराधिक कृत्यों में लगे हुए थे और सिटी की खजाने की तिजोरियों को लूटा जा रहा था।

प्रस्ताव 42 संविधान में सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही हैं को जानने के जनसामान्य के इस नागरिक अधिकार को दृढ़ता प्रदान करेगा। यह राज्य के कानूनों के साथ ऐसी स्वतंत्र ताकत जोड़ेगा जिसके अनुसार स्थानीय सरकारों के लिए खुली बैठक और सार्वजनिक रिकॉर्ड सम्बंधी कानूनों और भविष्य में विधानमंडल के द्वारा उन कानूनों में किये जाने वाले बदलावों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

प्रस्ताव 42 ऐसी सम्भावना को खत्म करेगा कि स्थानीय संस्थाएं सार्वजनिक जानकारी के लिए किये गये किसी अनुरोध के लिए इंकार कर सकती हों या लागत के आधार पर किसी बैठक में दरवाजा बंद कर सकती हों। जैसा Thomas Jefferson ने कहा, "सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है।" नौकरशाहों को बतायें कि लोगों को—न किन सरकार को—यह तय करना चाहिये कि हमें क्या जानने की ज़रूरत है। प्रस्ताव 42 पर हाँ यानि पक्ष में वोट दें।

MARK LENO, सदस्य California राज्य सीनेट
THOMAS W. NEWTON, कार्यकारी निदेशक
California Newspaper Publishers Association

★ प्रस्ताव 42 के पक्ष में दिये गये तर्क का खंडन ★

प्रस्तावक बुनियादी रूप से सही हैं कि *"प्रस्ताव 42 इस सम्भावना को खत्म करेगा कि स्थानीय संस्थायें"* [वैध रूप से] *सार्वजनिक जानकारी हेतु किये गये किसी अनुरोध के लिए इंकार कर सकती हैं या राज्य के इन कानूनों के अनुपालन की लागत" के* आधार पर किसी बैठक में दरवाजा बंद कर सकती हैं। यह ऐसा अनुपालन की लागत को स्थानीय सरकारों पर लगा कर करेगा। एक विकल्प यह हो सकता है कि राज्य सरकार भुगतान करे।

बहुत से वर्षों तक, मैंने राज्य और स्थानीय मतपत्र के विधेयकों के खिलाफ तर्क प्रदान किये हैं ताकि मतदाताओं को मतदान करने से पहले विधेयकों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके।

मैंने स्थानीय स्तर पर निर्णय-लेने की क्रिया को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करने के प्रयास में California सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम और खुली बैठक सम्बन्धी कानूनों का भी उपयोग किया है। जब उन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, तो एक दीवानी यानि सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है, और इसमें शामिल शासकीय कदाचार काउंटी की नागरिक ग्रैंड जूरी को रिपोर्ट किया जा सकता है।

हालाँकि, व्यक्तियों की अन्तर पैदा करने की योग्यता को—स्थानीय स्तर पर भी—हाल के वर्षों में *बड़े पैसे* के प्रभाव से और समूचे California में उन क्षेत्रीय पदों के लिए *कभी भी निर्वाचित नहीं किये गये* बोर्ड सदस्यों की अगुवाई वाली विभिन्न *क्षेत्रीय संस्थाओं* के सशक्तिकरण से कमजोर कर दिया गया है।

उदाहरण के लिए, San Francisco खाड़ी क्षेत्र में, क्षेत्रीय संस्थाओं ने बस ऐसी योजनायें अपना ली हैं जो दुनिया भर से आने वाले लाखों नये निवासियों को मौजूदा महानगरीय परिवहन गलियारों के अन्दर ठसाठस भर देंगी। केवल-बस वाली लेन बनायी जा रही हैं। HOV (हाई ऑक्युपैंसी व्हिकल) लेन्स को "एक्सप्रेस लेन्स" में बदला जा रहा है जो टोल-दाताओं को भी अनुमति प्रदान करती हैं।

आने वाले वर्षों में फ्रीवे पर सभी लेन्स *टोल लेन्स* बन सकती हैं। ऐसा देश भर में हो रहा है।

GARY WESLEY

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखको के विचार हैं और किसी भी आधिकारिक संस्था के द्वारा सटीकता के लिए उनकी जाँच नहीं की गयी है।

★ प्रस्ताव 42 के खिलाफ तर्क ★

स्थानीय सरकारें कर्मचारियों और राजनेताओं के द्वारा चलायी जाती हैं जो हो सकता है कि जानकारी बांटने या निर्णय लेने से पहले जनसामान्य से इनपुट प्राप्त करना चाहें या नहीं चाहें।

2004 में, California के मतदाताओं ने राज्य के ऐसे कानूनों के रोल बैक किये जाने को रोकने के लिये तैयार किये गये एक पहल सम्बन्धी राज्य के संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी जिसने बहुत से सार्वजनिक रिकॉर्ड की सुलभता की *गारंटी दी* और*अनिवार्य बनाया* कि स्थानीय सरकारों के विधायी निकायों की बैठकें आमतौर पर सार्वजनिक हों और यह भी कि स्थानीय निकायों के निर्णय केवल जनसामान्य के इनपुट के लिये एक अवसर दिये जाने के बाद ही लिये जा सकते हों *(California संविधान, अनुच्छेद I, धारा 3(b))।*

कुछ स्थानीय सरकारों ने यह आपत्ति करके जवाब दिया कि नये संवैधानिक प्रावधान ने राज्य के संविधान के *(अनुच्छेद XIII B, धारा 6)* के एक दूसरे प्रावधान, जिसके अनुसार यह आवश्यक है कि राज्य स्थानीय सरकारों को राज्य के नये जनादेशों को लागू करने की लागत का भुगतान करे, की जगह नहीं ली।

प्रस्ताव 42 California के संविधान को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित करेगा कि राज्य को किसी स्थानीय सरकार को स्थानीय सरकारों के लिए लागू खुली बैठक सम्बन्धी कानून (*Brown* ऐक्ट—सरकारी संहिता की धारायें 54950–54963) या *सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम* (सरकारी संहिता की धारायें 6250–6270) जैसी लिखी या बाद में बदली गयी हैं—जब तक कि किसी बदलाव *"में यह प्रदर्शित करता हुआ निष्कर्ष शामिल नहीं हो कि वैधानिक अधिनियमन सार्वजनिक सुलभता और इनपुट की संवैधानिक गारंटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है"* का अनुपालन करने की लागत के लिए भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है।

इस प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत मुख्य मुद्दा है कि क्या मतदाता मानते हैं कि राज्य के इन महत्वपूर्ण कानूनों का अनुपालन करने की लागत स्थानीय सरकारों के द्वारा वहन की जाये या राज्य सरकार के द्वारा।

GARY WESLEY

★ प्रस्ताव 42 के खिलाफ दिये गये तर्क का खंडन ★

हमारा लोकतंत्र सरकार में जानकारी पर आधारित और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। प्रस्ताव 42 एक ऐसा सरल विधेयक है जो यह जानने के मूल अधिकार की रक्षा करता है कि सरकार हमारा कारोबार कैसे संचालित करती है।

प्रस्ताव 42 के खिलाफ Mr. Wesley के प्राथमिक तर्क में बहुत से तथ्यों का जिक्र किया गया है—जिनमें से अधिकांश से हम सहमत हैं—लेकिन इसमें इस बारे में कोई खास तर्क नहीं दिया गया है कि California सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम और Ralph M. Brown खुली बैठक कानून जैसे आपकी जानकारी की आजादी के कानूनों के अनुपालन से जुड़ी उनकी लागतों के भुगतान के लिए स्थानीय सरकारी संस्थाओं को राज्य का मुँह क्यों ताकना चाहिये।

खुली बैठकों और सार्वजनिक रिकॉर्ड की सुलभता की आवश्यकता वाले हमारे राज्य और स्थानीय कानूनों का अनुपालन संवैधानिक सिद्धांत का मामला है।

सच्चाई यह है कि प्रत्येक राजकीय संस्था सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम और Bagley-Keene ऐक्ट, जो Brown ऐक्ट के जैसा ही है और जिसमें राज्य बोर्ड और आयोगों के लिए खुले में मिलना और सार्वजनिक सत्र आवश्यक हैं, के अनुपालन की अपनी लागतों का खुद भुगतान करती है।

जब संस्थायें अनुपालन की अपनी लागतों का भुगतान करती हैं, तो उन लागतों को कम रखने के लिए नये ढंग निकालने के लिए अंतर्निहित प्रोत्साहन है, जैसे रिकॉर्ड के लिए अनुरोध प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना तथा आसान सार्वजनिक सुलभता के लिए ऐसे रिकॉर्ड को ऑनलाइन रखना जिनके लिए आमतौर पर अनुरोध किया जाता है। अगर राज्य स्थानीय संस्थाओं को इन बुनियादी महत्वपूर्ण कानूनों का अनुपालन करने के विशुद्ध स्थानीय दायित्व के लिए भुगतान करता है, तो सुधार करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

यह सरल है; राज्य अपनी खुद की लागतों का भुगतान करता है और स्थानीय संस्थाओं को उनकी अपनी लागतों का भुगतान करना चाहिये।

जानने के अपने नागरिक अधिकार की रक्षा करें और प्रस्ताव 42 पर हाँ यानि पक्ष में मतदान करें।

JAMES W. EWERT, जनरल काउन्सल
California Newspaper Publishers Association

DONNA FRYE, प्रेसिडेंट
Californians Aware

JENNIFER A. WAGGONER, प्रेसिडेंट
League of Women Voters of California

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखको के विचार हैं और किसी भी आधिकारिक संस्था के द्वारा सटीकता के लिए उनकी जाँच नहीं की गयी है।